The Minister of Planning (Shri Asoka Mehta): In discussions with the Planning Commission, the State Governments agreed to consider the proposal for raising additional resources for the 1966-67 Plan through changes in urban immovable property tax or levy of such a tax in case the State Government concerned was not levying it already. The U.P. Government has since introduced certain changes in the urban immovable property tax levied in that State and the Gujarat Government has increased the education cess on lands and buildings in urban areas. The Bihar Government has also introduced a Bill in the State Legislature for imposing a tax on non-agricultural urban land. Besides, the Mysore Government has recently placed a Bill before the State Legislature for levying a tax on urban land and the Kerala Government is actively considering the matter. Information for other States is not yet available.

Land Reforms Measures

*191. **Shri Linga Reddy:**
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri Warior:
Shri Indrajit Gupta:
Shri Vasudevan Nair:
Shri Prabhat Kar:
Shri Gopal Datt Mengi:
Shri P. R. Chakraverti:
Shri K. N. Tiwary:
Shri Rameshwar Tantia:
Shri Himatsingka:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Lahtan Chaudhry:
Shri P. C. Borooah:

Will the Minister of **Planning** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 309 on the 18th November, 1965 and state:

(a) the further progress made in implementing Land Reforms measures in the States;

(b) the reasons for the delay in the matter of introduction of land reforms in the States; and

(c) the suggestions made by the Planning Commission to the States in this regard?

The Minister of Planning (Shri Asoka Mehta): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-5566/66].

Development of Hill Areas

*192. **Shri Hem Raj:**
Shri Yashpal Singh:

Will the Minister of **Planning** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 448 on the 25th November, 1965 and state:

(a) the progress since made by the Steering Committee of the Planning Commission for the development of hill areas;

(b) whether the Report has been finalised;

(c) if so, its recommendations; and

(d) whether a copy of the Report will be laid on the Table?

The Minister of Planning Shri Asoka Mehta): (a) to (d). The Steering Committee has not yet completed the examination of the reports of the Working Groups. Two of the Working Group reports viz. those on Vilage and Small Industry and on Transport, have not yet been received by the Steering Committee.

राज्यों द्वारा केन्द्रीय ऋण की वापसी

*193. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्रीय ऋण की वापसी के सम्बन्ध में और छूटों की याचना की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख). कुछ राज्य सरकारें, कुछ ऋणों की शर्तों आदि में संशोधन करने के लिए समय-समय पर अनुरोध करती रहती हैं । इन अनुरोधों पर, प्रत्येक मामले के गुण-दोष के अनुसार विचार किया जाता है ।

भू-राजस्व

***194. श्री किशन पटनायक :**
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से राज्य साधनों को एकत्रित करने के लिए 1966-67 में भू-राजस्व तथा सिंचाई दरों में वृद्धि करने के सम्बन्ध में सहमत नहीं हुए है;

(ख) उन राज्यों ने क्या कारण बताये है; और

(ग) साधनों में कमी को पूरा करने के सम्बन्ध में इन राज्यों द्वारा क्या उपाय काम में लाये जा रहे हैं ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) योजना आयोग से विचार विनिमय के दौरान, आन्ध्र प्रदेश तथा असम सरकारों ने, भू-राजस्व या सिंचाई दरों में वृद्धि करने के लिए कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं रखे हैं ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने जो कारण बताये हैं वे निम्न प्रकार हैं :—

(1) 1962-63 में भू-राजस्व की दरें काफी बढ़ाई गई । इसके अलावा, गन्ना क्षेत्र की दरें 1965-66 में और बढ़ाई गईं;

(2) आन्ध्र प्रदेश में भू-राजस्व की दरें पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा सामान्यतया काफी ज्यादा हैं ;

(3) सिंचाई दरों से सम्बन्धित कानून हाल ही में उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया जा चुका है; और

(4) चालू वर्ष में खराब मौसम के कारण राज्य की फसल पर बुरा प्रभाव पड़ा है ।

जहां तक असम का सम्बन्ध है, राज्य सरकार ने 1966-67 की राज्य योजना के लिए अतिरिक्त साधनों को जुटाने के एक भाग के रूप में जिन कानूनों को बनाया है, उन्हें अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) प्रेस रिपोर्ट के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अपने 1966-67 के बजट में किसी भी अतिरिक्त कराधान कानून की घोषणा नहीं की है । सूचना मिली है कि राज्य सरकार व्यय में कटौती करना चाहती है, राजस्व संग्रह में सुधार करना चाहती है और प्रतिभूतियों के संचित निधि से धन लेना चाहती है । असम की स्थिति का ज्ञान तब हो सकेगा जब राज्य विधान सभा को राज्य का 1966-67 का बजट प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

Rising Prices of Commodities

***195. Shri S. M. Banerjee:**
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri P. C. Borooah:
Shri Ram Harkh Yadav:
Shri Murli Manohar:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the prices of all essential commodities have gone up during December, 1965 and January, 1966;

(b) whether prices are daily going up despite the steps taken by Government; and